प्रिलिम्स फैक्ट्स (17 Dec, 2020)

drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/17-12-2020/print

प्रिलिम्स फैक्ट: 17 दिसंबर, 2020

हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मान्यता के लिये योजना

हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों की मान्यता के लिये योजना

Scheme for Approval of Hygiene Rating Audit Agencies

हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद (**Quality Council of India-** QCI) स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसियों (**Hygiene Rating Audit Agencies-** HRAA) को मंज़ूरी देने के लिये एक योजना लेकर आई है।

यह कदम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India's- FSSAI) की खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना का एक हिस्सा है।

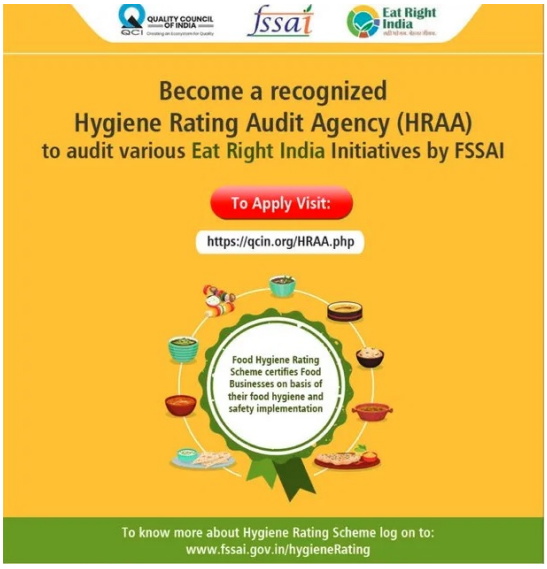

प्रमुख बिंदु:

योजना के संबंध में:

- यह देश में मान्यता प्राप्त HRAA की संख्या को बढ़ाकर **स्वच्छता रेटिंग में वृद्धि करेगी**।
- मान्यता प्राप्त HRAA खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और प्रक्रियाओं के बारे में FSSAI द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करेगी।

खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना:

- इसकी शुरुआत FSSAI द्वारा की गई थी। यह उपभोक्ताओं को सीधे या ऑफ-प्रिमाइस (Off-premise) भोजन की आपूर्ति करने वाले **खाद्य व्यवसायों के लिये एक प्रमाणन प्रणाली** है।
- खाद्य स्वच्छता योजना उपभोक्ताओं ko जागरूक करने और खाद्य व्यापार ऑपरेटरों के मध्य स्वत: अनुपालन की संस्कृति विकसित करने में सहायक होगी।
- इससे खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ भोजन की मांग में भी बढ़ोतरी होगी।
- इसके अलावा भारतीय उपभोक्ताओं और खाद्य सेवा ऑपरेटरों के बीच आपसी विश्वास को मज़बूती प्रदान करने के साथ-साथ भोजन की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलेगी।
- इस प्रकार के मानक और उनके मूल्यांकन से उपभोक्ताओं द्वारा सेवा प्रदाताओं के समक्ष खाद्य भोजन की मांग में वृद्धि के साथ ही विश्वास को बढ़ावा मिलता है।
- यह योजना खाद्य पदार्थों की विक्री करने वाले प्रतिष्ठानों (जैसे- होटल, रेस्तराँ, कैफेटेरिया, ढाबों), मिठाई की दुकानों, बेकरी, मांस खुदरा स्टोर आदि पर लागू होती है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद

(Quality Council of India- QCI)

- वर्ष 1997 में स्थापित QCI भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी में संगठनों की स्थापना हेतु भारत सरकार का एक अग्रणी प्रयोग है।
    - भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की थी।
    - भारतीय उद्योग की QCI में तीन प्रमुख उद्योग संघों अर्थात् एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फिक्की (FICCI) को दर्शाया गया है।
- इस संगठन की स्थापना के अनुरूप प्रत्यायन निकायों के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन ढाँचे की स्थापना एवं उनके संचालन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता संवर्द्धन के क्षेत्र में प्रत्यायन उपलब्ध कराने व्यवस्था की गई थी।
- प्रत्यायन ढाँचे के तौर पर भूमिका अदा करने के अलावा यह '**राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड**' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABCB) द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के ज़रिये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (ISO 14001 शृंखला), **खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली** (ISO 22000 शृंखला) तथा उत्पाद प्रमाणन एवं निरीक्षण निकायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित करता है।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 17 दिसंबर, 2020

बोरिस जॉनसन

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वर्ष

2019 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात् बोरिस जॉनसन की यह भारत यात्रा रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में में हिस्सा लेने के लिये भारत आने वाले बोरिस जॉनसन दूसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे, इससे पूर्व वर्ष 1993 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में और अधिक सुधार होने की उम्मीद है। विदित हो कि यह यात्रा ऐसे समय में की जा रही है, जब ब्रेक्ज़िट (Brexit) की प्रक्रिया तकरीबन पूर्ण होने वाली है, ऐसे में ब्रिटेन को व्यापार समेत विभिन्न पहलुओं पर नए साझीदारों की आवश्यकता है और भारत इस भूमिका को बखूबी निभा सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री को अगले वर्ष आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया है, जिसकी मेज़बानी ब्रिटेन द्वारा की जा रही है। भारत उन तीन देशों में से एक है जिन्हें ब्रिटेन द्वारा G7 शिखर सम्मेलन के लिये अतिथि राष्ट्र के तौर पर आमंत्रित किया गया है, अन्य दो देश ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया हैं।

चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल लाइन

भारत-बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से भारत-बांग्लादेश के बीच चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसी के साथ भारत-बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद पुनः चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल संपर्क खोल दिया जाएगा, जिसे वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। हल्दीबाड़ी (पश्चिम बंगाल) से चिलाहाटी (बांग्लादेश) तक की यह रेलवे लाइन अब दोनों देशों के बीच आवागमन को आसान बनाने, आपसी संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिये पुनः चालू की जा रही है। साथ ही यह रेलवे लाइन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगी। फिलहाल यह रेल ट्रैक केवल माल ढुलाई के लिये उपलब्ध होगा, किंतु जल्द ही बुनियादी ढाँचे की व्यवस्था के बाद दोनों तरफ से यात्रियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी।

यूवी-एलईडी और कोरोना वायरस

इज़राइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने अपने एक शोध में सिद्ध किया है कि कोरोना वायरस को पराबैंगनी-प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी यूवी-एलईडी (UV-LEDs) का उपयोग करके आसानी से मारा जा सकता है। शोध के दौरान कोरोना वायरस परिवार के सभी सदस्यों, जिसमें SARS-CoV-2 भी शामिल है, पर यूवी-एलईडी विकिरण की कीटाणुशोधन क्षमता का आकलन किया गया। शोध में पाया गया कि पराबैंगनी-प्रकाश वाले एलईडी (LED) बल्बों का उपयोग करके कोरोना वायरस को आसानी से खत्म किया जा सकता है। हालाँकि शोधकर्त्ताओं ने स्पष्ट किया है कि घरों के अंदर की सतह को कीटाणुरहित करने के लिये इस पद्धति का प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। इस पद्धति का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिये ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाना आवश्यक है, जिससे कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर प्रकाश के संपर्क में न आए।

हिमालय के लिये क्षेत्रीय जलवायु केंद्र

भारत हिमालयी पर्वत क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो न केवल देश के भीतर मौसम की जानकारी संबंधी सेवाएँ प्रदान करेगा बल्कि आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों में भी इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। ज्ञात हो कि चीन भी हिमालयी क्षेत्र में इसी प्रकार का एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है। यह क्षेत्रीय जलवायु केंद्र हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों विशेष तौर पर किसानों और

जनजातियों के लिये मौसम से संबंधित सेवाएँ प्रदान करेगा। हिमालय के आकार और भारत की जलवायु, आपदा प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र तथा कई अन्य गतिविधियों में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के चलते इसे 'विश्व का तीसरा ध्रुव' भी कहा जाता है।